विवरण

1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण-स्थल पर मूल्य (उत्पाद शुल्क सहित)

रुपए/विक्रय इकाई

	1991	1992	%वृद्धि	1993	%वृद्धि	1994	%वृद्धि	1995	%वृद्धि
एम एस-87	11180.09	13416.11	20.00%	14413.21	7.43%	15413.21	6.94%	15413.21	.00%
एचएसडी	4541.91	4541.91	.00%	5539.01	21.95%	6289.01	13.54%	6289.01	.00%
एसकेडी (घरेलू)	2446.16	2201.54	-10.00%	2201.54	.00%	2201.54	.00%	2201.54	.00%
एल पी जी (पैकड घरेलू)	3448.98	4130.78	20.00%	5135.88	24.09%	5840.11	13.71%	5840.11	.00%

Privatisation of Marketing of Petroleum Products

1703. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of State Governments have written to the Central Government against the decision of the latter to allow private companies to market kerosene and LPG without any restrictions; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) and (b) While the Ministry had received a message from the Government of West Bengal in February, 1993, protesting against the introduction of Parallel Marketing of Kerosene and LPG and expressing apprehensions of diversion of Kerosene under Public Distribution system (PDS) and subsidised LPG into the open market, and requested immediate reversal of the decision, the West Bengal Government has in April, 1994 issued orders and guidelines to its officials regarding the implementation of Parallel Marketing System in the state.

The Parallel Marketing System enables greater availability of kerosene and LPG in the free market. Necessary safeguards have been taken to prevent diversion of PDS kerosene and subsidised LPG into the Parallel Marketing Network. Parallel Marketing System is now working successfully in different States. Further to protect the interest of the consumers and to educate them about the capabilities and credibilities of the parallel marketeers, rating of parallel marketeers has been introduced from June, 1995, under which the Parallel marketeers have to obtain rating from a nominated agency and have to declare and publish the same in all communications.

दिल्ली में रेड-लाईन बसों द्वारा की गई दुर्घटनाएं

1704. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छहः महीनों के दौरान दिल्ली में रेड लाईन बसों द्वारा की गई दुर्घटनाओं के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा लगातार आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी नहीं आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी दुर्घनाओं को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) 1.5.95 से 15.11.95 तक रेड लाइन बसें दिल्ली में 590 दुर्घनाओं के लिए जिम्मेदार थीं।

(ख) जी हां।

(ग) रेड लाइन बसों से होने वाली दुर्घटनाओं के

मुख्य कारण अन्धाधुन्ध वाहन चलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन, तेज गति, ड्राइवरों की थकान, बसों में अधिक सवारियां होना है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिल्ली में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय

1. परिवहन विभाग, दिल्ली ने वैज्ञानिक विधि से चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया है।

2. ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

3. दिल्ली पुलिस ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) यातायात नियमों और विनियमों का सख्ती से अनुपालन जिसमें परमिटों का निलम्बन किया जाना शामिल है।

(ii) अंधाधुन्ध और लापरवाही से वाहन चलाने, लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और लाल बत्ती पार करने के विरुद्ध विशेष अभियान चलाना।

(iii) नोटिस जारी करके उल्लंघन कर्त्ताओं का नियमित अभियोजन।

(iv) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में यातायात संकेत/ब्लिंकर लगाना।

(v) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में अधिक यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती।

(vi) अन्धाधुन्ध वाहन चलाने वाले ड्राइवरों की गिरफ्तारी।

(vii) अत्याधुनिक उपकरण अर्थात् एल्कोमीटर और रडार गन से अभियोजन।

(viii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए विभिन्न स्थलों पर "चल प्रदर्शन वैन" ले जाना।

(ix) सड़क सुरक्षा संबंधी साहित्य का वितरण।

Discussion with WTO Group for Trade in Telecommunications

1705. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the trade in basic telecommunication services is being discussed in the WTO group;

(b) whether it is also a fact that these discussions are supposed to be concluded only by the end of April 1996;

(c) if so, whether it is a fact that some of the concessions given to foreign telecom companies in the basic services imply a squandering of negotiating advantage for the Indian team which is engaged in the WTO process; and

(d) if so, the details of the provisions in the draft which is being discussed on issues like foreign equity, security parametres, nature of regulatory authority etc.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir

(c) No, Sir.

(d) Does not arise in view of (C).

Sending Mail Through State Transport Buses in Maharshtra

1706. SHRI N. GIRI PRASAD: Will the minister of COMMUNICATIONS be pleased to state.

(a) the total number of State Transport Buses in Maharashtra being used to send Mail every day;

(b) whether the State Transport Buses have announced to have their own Parcel Scheme; if so, the possible difficulties to use the State Transport Buses from Nagpur, Wardha to Aurangabad, Jalna and Nanded; and

(c) how many Transport Buses are used for special post from Nagpur to various towns in Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE OF THE